



अधिकतम : 33°C
न्यूनतम : 19°C

अबरे छुपाता नहीं, छपता है

शाह टाइम्स

मेरठ, शनिवार 18 अप्रैल 2026 मेरठ संस्करण: वर्ष 19 अंक 316 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com

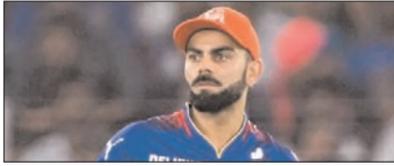
वैसाख शुक्ल पक्ष 1 विक्रमी सम्वत् 2083

29 श्याल 1447 हिजरी

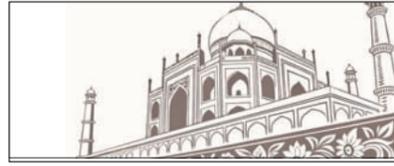
नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुगदाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



उप में अपराध नियंत्रण के लिए 500 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तैयार पेज 2



बेंगलुरु-दिल्ली के बीच बड़े मुकाबले में विराट पर रहेगी सबकी नजरें खेल टाइम्स



घरोघरों में घड़कता भारतीय इतिहास सम्पादकीय



ईरान से समझौते के लिए खुद पाकिस्तान जाएंगे ट्रम्प! पेज 12

संक्षिप्त समाचार

यूपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू, बांदा में पारा 44 डिग्री के पार
नई दिल्ली। देश के मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी जारी है। यूपी के बांदा में पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस, एम्पी के नर्मदापुरम में 43 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान के बाड़मेर में 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इधर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरने से मंडी में रखा अनाज भीगा गया। मौसम विभाग के मुताबिक, जयपुर समेत 5 से ज्यादा जिलों में बरसात हो सकती है। हरियाणा में भी शुक्रवार दोपहर को बारिश और ओले गिरने। छत्तीसगढ़ में हीटवेव के कारण 11 दिन पहले स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर-डिंडोरी में भी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7 से 12 बजे तक कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड में अगले 3 दिन लू का अलर्ट है।

सबरीमाला मंदिर केस में 5वें दिन भी सुनवाई जारी रही
नई दिल्ली। केस के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन भी सुनवाई जारी रही। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट राजीव धवन ने कोर्ट से कहा कि आस्था या विश्वास समर्थक के साथ हमेशा बदलते रहते हैं। यह बदलाव सिर्फ किसी कानून के बन जाने से नहीं आता, बल्कि यह बदलाव तो लोगों के बीच से ही उभरकर आता है। इससे पहले 9 जजों की बेंच ने 15 अप्रैल को सुनवाई में कहा था कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। साथ ही यह भी कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। वहीं मंदिर प्रशासन त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड (टीडीबी) ने कहा कि सबरीमाला कोई खिलौने की दुकान या रेस्टोरेंट का मामला नहीं है। यहां के देवता ब्रह्मचारी हैं। भारत में अय्या के लगभग 1,000 मंदिर हैं। अगर महिलाओं को दर्शन करना है, तो वहां जाएं।

सेना को सशक्त बनाने व रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल
नई दिल्ली। सेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे सैन्य संघर्ष और ऑपरेशन सिद्ध के अनुभवों के आधार पर सेना को हर तरह से सशक्त बनाने तथा उसकी जरूरतों को देश में ही पूरा करने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। सैन्य नेतृत्व ने मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन रोधी प्रणालियों के उपयोग सहित संचालन क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को वक्तव्य जारी कर कहा कि सेना के कमांडरों के 13 अप्रैल से शुरू हुए चार दिन के सम्मेलन की अध्यक्षता सेना प्रमुख ने की और इसमें शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने भाग लिया। सम्मेलन को कैबिनेट सचिव, प्रमुख रक्षा अधिकारी, रक्षा सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष तथा नौसेना प्रमुख सहित सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबोधित किया।

'भविष्य के लिए तैयार बल' बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप, सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता को बंध घोषित किया है।

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोला, डोनाल्ड ट्रम्प बोले शुक्रिया

तेहरान/वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और लेबनान में लागू युद्धविराम के बीच ईरान ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। ईरान ने सीजफायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है।



होर्मुज स्ट्रेट

विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। यह फंसला लेबनान में युद्धविराम के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि जहाज एक सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे, जिसे ईरान के पोर्ट्स और मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है, ताकि सफर के दौरान कोई खतरा न हो। अराघची ने कहा कि

इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। विदेश मंत्री के अनुसार, यह निर्णय युद्धविराम अवधि के शेष समय के लिए लागू रहेगा और पहले से घोषित समन्वित मार्ग के

तहत सभी व्यापारिक जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। यह मार्ग ईरान के पोर्ट्स एंड मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया गया है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, जहां

से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग को खोलने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और शिपिंग उद्योग के लिए राहत भरा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम क्षेत्रीय

तनाव को कम करने और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्विटर पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही होर्मुज

स्ट्रेट खुल गया है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी और यह सिर्फ ईरान पर लागू होगी। ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिचड (संवर्धित) यूरैनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है।

तरनजीत संघ ने हमेशा अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। दिल्ली की प्रगति का नेतृत्व करने और वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सफलता की कामना करता हूँ। तरनजीत सिंह संघ, जो दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं, फरवरी 2020 से जनवरी 2024 तक अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत रहे।

महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरा

21 घंटे हुई बिल पर चर्चा, पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े

शाह टाइम्स ब्यूरो

54 वोट से गिरा बिल, 11 साल के शासन के दौरान पहली बार मोदी सरकार बिल पास नहीं करा पाई, बेअसर रही शाह की एक घंटा स्पीच

परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 पर सरकार ने वोटिंग कराने से किया इन्कार

नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान के 3 संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। 21 घंटे की चर्चा के बाद सबसे पहले संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई। संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 के जरिये 850 सीटें करने का प्रावधान था। इसके पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल 54 वोट से गिर गया। इसके बाद सरकार ने बाकी 2 बिल-परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 पर वोटिंग कराने से इन्कार कर दिया। 11 साल के शासन में यह पहला



विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया, बहुत खेद की बात: किरन रिजिजू

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने से जुड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था। इसी पर यह नतीजा आया है। विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। आपने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम उन्हें अधिकार दिलाकर ही रहेंगे।

हमले को हरा दिया है। हमने साफ तौर पर कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका है। शाह ने

कहा कि मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था। आपकी जिम्मेदारी है कि सदन की गरिमा बनी रहती। वे कहते हैं कायर हैं, सैंडर कर रहे हैं।

उप सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के विरोध और मजदूरी बढ़ाने की मांग के बाद न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि कर दी है। एक अप्रैल 2026 से नई दरें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

एक अप्रैल 2026 से नई दरें लागू करने की अधिसूचना जारी

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश को तीन श्रेणियों में बांटकर अलग-अलग मजदूरी दरें तय की गई हैं। सरकार के फ्रैसले में नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को श्रेणी-1 में रखा गया है, जबकि अन्य नगर निगम वाले जिले श्रेणी-2 और शेष जिले श्रेणी-3 में शामिल किए गए हैं। नई दरों के लागू होने से सबसे अधिक लाभ श्रेणी-1 के श्रमिकों को मिलेगा। नई दरों के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में

कम से कम 1,300 रुपये से अधिक की वृद्धि सुनिश्चित की गई है। प्रदेश सरकार ने 13 अप्रैल को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, जिसने विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श के बाद संशोधित दरों की सिफारिश की। साथ ही श्रमिकों के वेतन से केवल 10 प्रतिशत और इंसआई की ही कटौती मान्य होगी। श्रम विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से, साथ ही बोनस और ग्रेंच्युटी का भुगतान नियमानुसार किया जाए। यदि किसी सांविदाकार द्वारा समय पर वेतन नहीं दिया जाता या कम भुगतान किया जाता है, तो उस पर न केवल वसूली की कार्यवाही होगी, बल्कि लाइसेंस निरस्त कर ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।

जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने संविधान पर हुए इस

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

इसके बाद अब राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। दोहरी नागरिकता के मामले में शुक्रवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। यह मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

इसके बाद अब राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। दोहरी नागरिकता के मामले में शुक्रवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। यह मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

इसके बाद अब राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। दोहरी नागरिकता के मामले में शुक्रवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। यह मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ

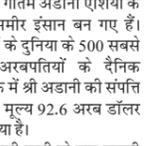
सोबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सोबीआई करेगी। गौतमबुद्ध है कि कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विनय शिशिर ने यह याचिका दाखिल की थी। यानी लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी।

गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर इंसान

शाह टाइम्स ब्यूरो

अडानी की संपत्ति का शुद्ध मूल्य 92.6 अरब डॉलर आंका गया

मुकेश अंबानी को पछाड़कर अडानी ने यह उपलब्धि हासिल की



नई दिल्ली। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। ब्लूमबर्ग के दुनिया के 500 सबसे अमीर अरबपतियों के दैनिक सूचकांक में श्री अडानी की संपत्ति का शुद्ध मूल्य 92.6 अरब डॉलर आंका गया है।



पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। पिछली सूची के बाद श्री अंबानी की संपत्ति में 7.67 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है और यह

और ये सभी औद्योगिकी कंपनियां हैं। जाने-माने उद्योगपति एलन मस्क 656 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर हैं। उनके बाद क्रमशः लैरी पेज, जेफ बेजोस, सर्गेई ब्रिन और माक जुकर्बर्ग रहे। शीर्ष 20 में अमेरिका के अलावा भारत के दो और फ्रांस, मैक्सिको तथा स्पेन की एक-एक कंपनियां शामिल हैं।

90.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पिछली सूची में अब 20वें स्थान पर हैं। इस सूची में पहले आठ स्थान पर अमेरिका का कब्जा है

लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश

नई दिल्ली। राज्यसभा के

मनोनीत सदस्य हरिवंश को शुक्रवार को लगातार तीसरी बार उच्च सदन के उप सभापति के पद पर ध्वनिमत से चुन लिया गया।

नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने हरिवंश को उप सभापति चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका भारतीय जनता पार्टी की सदस्य एस. फांगोनन कोट्याक ने समर्थन किया। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वह इस पद पर लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। प्रस्ताव रखे

विपक्ष के सदस्यों को सभापति ने कुछ कहने की अनुमति नहीं दी

जाने के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने इस संबंध में कुछ कहना चाहा, लेकिन सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। विपक्ष की ओर से इस पद के लिए किसी का नामांकन नहीं किया गया था। पहला अवसर है, जब किसी मनोनीत सदस्य को सदन का उप सभापति चुना गया है।

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

एक नजर

उमना फातिमा गोल्ड मेडल से सम्मानित



किरतरपुरा क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि काजी तारिक अली की पुत्री उमना फातिमा ने जामिया मस्जिद से एम.एससी (बायोमैडिकल साइंस) अंतिम वर्ष में प्रथम स्थान हासिल कर पब्लिक व क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

होम डिलीवरी की लिस्ट फाइन पर हांगामा



नजीबाबाद। उप जिलाधिकारी शरीफुल क़ुमार के आदेश पर होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर वितरण की व्यवस्था के वायवजूद इंडियन गैस एजेंसी के गोदापूर पर हांगामा हो गया।

छात्राओं को अधिनियम की जानकारी दी



बिजनौर। आरबीडी डिप्टी कलेक्टर प्र.शरत ल्यागी के निदेश पर महिला आरक्षण अधिनियम 2023 (नारी शक्ति बंधन अधिनियम) के अंतर्गत प्रथम बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

एजुकोल का रिजल्ट रहा शत प्रतिशत



धामपुर। एजुकोल द गवर्ल् स्कूल में कक्षा दसवीं बाईं का परीक्षाफल गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शत प्रतिशत रहा।

मिट्टी से लदे वाहनों से उड़ रही धूल

शाह टाइम्स संवाददाता नजीबाबाद। बुदको रोड इन दिनों धूल के गुबार और अनियंत्रित रफ्तार का पर्याय बन गई है।



स्कूली बच्चों की सेहत पर संकट

वाहन तेज रफ्तार से निकलते हैं। नियमानुसार मिट्टी परिवहन के दौरान उस तिरपाल से ढकना अनिवार्य है।

दूरघाता कम हो जाती है। जिससे दुर्घटना का भय बचता है। साथ ही बच्चों में सांस की तकलीफ और अस्थि में जलन जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं।

प्यूचर चिल्ड्रन एकेडमी का शानदार प्रदर्शन

शाह टाइम्स संवाददाता शिवलाहा कला। प्यूचर चिल्ड्रन एकेडमी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि विद्यार्थियों के कक्षा 10 के विद्यार्थियों का परिणाम सीबीसीएसई द्वारा घोषित किया गया।



उनके उज्वल परिणाम की कामना की है। साथ ही सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, अधिपत्यकों के सहयोग को दिया गया है।

तीन दिवसीय पर्यवेक्षक प्रशिक्षण का शुभारंभ

व्यावहारिक समस्याओं और उनके निराकरण पर विस्तृत चर्चा

शाह टाइम्स/जिला बिजनौर। एडीएम/बिजला जनांगना अधिकारी वाय्या सिंह के दिशा निर्देश में आज तहसील एवं नगर निकाय स्तर पर तीन दिवसीय प्रमाण एवं पर्यवेक्षक की ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।



ट्रेनिंग के माध्यम से प्रणालियों को संबोधित किया। प्रणालियों को निर्देशित किया गया कि वे घर-घर व्यवहार कर और प्रत्येक कॉलम आम जनमानस के साथ मृदु व्यवहार करें और प्रत्येक कॉलम को सावधानीपूर्वक भरें।

उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जानकारी दी

शाह टाइम्स संवाददाता नजीबा। कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत को कम करने और मिट्टी की सेहत सुधारने के उद्देश्य से आज ग्राम चन्द्रपुरा (कोतवाली) में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



यूरिया-डीएपी पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भूमि की जलधारण क्षमता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी कृषि योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की हुंकार

शाह टाइम्स व्यूरो बिजनौर। जिला कांग्रेस कमेट्री द्वारा आर.के. फारम में संगठन सुबह एवं समीक्षा की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की राजनीति में एक स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया।



नारिकों के मुहों से। उन्होंने कार्यकर्ताओं के जन्मे और संघर्षशीलता की सरहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी लाकट के साथ जनता के हक की लड़ाई लड़ रहा है।

बैठक की समीक्षा एएससीसीसीएचए एवं परिचामी उदर प्रवेश प्रदारी प्रवेश नरवाल द्वारा किया गया। उन्होंने प्रदेश की परिस्थितियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की उदासीलता अब बदोशर नहीं की जा सकती।

आठ विधानसभा सीटों पर तेज होगी तैयारी

विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ काम करने का आवाहन किया और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव, जो अब केवल लगभग आठ महीने दूर है के लिए पूरी तैयारी करने एवं संगठन को बुध स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जो इस बात का प्रमाण है कि जनता का विश्वास तेजी से कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में संगठन और भी सक्रिय होकर उभरेगा।

एक नजर

विवेक में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम



बिजनौर। विवेक विश्वविद्यालय परिसर में आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम-प्रचार अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति दीवार और मानव श्रृंखला के कार्यक्रम आयोजित किए गए।



नजीबा। आगामी जनांगना 2027 के उज्वल क्रियाचक्रण के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज ग्रामपंच क्षेत्रों के लिए नियुक्त प्रमाणकों और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है।

गेहूं की फसल जलकर राख



होमपुर दीपा। खेत में आग लगने से किसान की फसल जलकर राख हो गई। इसके साथ ही गोवा प्रशासनाधीन क्षेत्रों में किसान सहायता सिंधु पुत्र बंधन को भी धोखा भोगने में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगा गई।

नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर संगोष्ठी



धामपुर। श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज एवं होस्टल पोलिसला में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

चुराई नकदी के साथ दबाओ

नजीबाबाद। थाना पुलिस ने क्षेत्र में एक घर से हजारी रूपए चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

कामकाजी परिस्थितियां!

भारत की औद्योगिक क्षमता के विस्तार से पुराने पड़ चुके बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा संयंत्र करीब-करीब अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे हैं, और उनके प्रबंधन में व्याप्त खामियों को मीडिया में अधिक कवरेज और राजनीतिक ध्यान मिल रहा है। संभव है कि ये इकाइयां लंबे समय से अपने कामगारों को खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों में झोंक रही हैं और लिहाजा पैदा होने वाले संकट पूरी तरह से आकस्मिक नहीं हैं। अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिक (कांटेक्ट लेबर) सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। कामगारों का एक बढ़ता हुआ हिस्सा उपकेन्दरों के जरिए काम पर रखे गए प्रवासी श्रमिकों का है। किसी आपदा के बाद ये कामगार और संचालक एक-दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। सुरक्षा संबंधी संकेत और नियमावली अक्सर कामगारों की मातृभाषा में उपलब्ध नहीं होते हैं। हाल ही में बायलर विस्फोट की घटनाओं में आई बाढ़ के पीछे की एक इंजीनियरिंग से जुड़ी हकीकत यह है कि बायलर कभी भी इस तरह अचानक खराब नहीं होते हैं। ये हादसे आमतौर पर बहुत ज्यादा दबाव, क्षमता में बदलाव (स्केलिंग), पानी के स्तर के कुप्रबंधन और/या फिर से सक्रिय करने संबंधी तनाव (रिवाइवल स्ट्रेस) की वजह से होते हैं। इनमें से हरेक कारक का जोखिम वक्त के साथ बढ़ता जाता है। कुल 20 लोगों की जिंदगी लील लेने वाले छत्तीसगढ़ के शक्ति संयंत्र में हुए बायलर विस्फोट और 2020 में विशाखापत्तनम गैस रिसाव एवं 2020 में नेवेली के एक ताप विद्युत केंद्र में हुए विस्फोट में काफी कुछ समानताएं हैं। विशाखापत्तनम वाले मामले में जहां लाकडाउन के बाद फिर से शुरू होने पर एक इकाई में सुरक्षा प्रणालियां निष्क्रिय या ठीक नहीं थीं, वहीं नेवेली वाले मामले में संयंत्र को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया ने विस्फोट को जन्म दिया। शक्ति संयंत्र को भी हाल ही में अधिग्रहित व चालू किया गया था और विस्फोट के वक्त वह अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा था। संचालन की इन अस्थिर स्थितियों में, विफलताएं अक्सर क्षणिक तापीय और दबाव संबंधी असंतुलन की वजह से होती हैं। हालांकि, व्यवहार में, न तो राष्ट्रीय बायलर निरीक्षण व्यवस्था और न ही नियामक ढांचा इन चरणों में निगरानी को बढ़ाता है। बायलर की स्थिति भले ही रोजाना बदलती रहती हो, लेकिन इनका प्रमाणन एक साल तक वैध रहता है। मौजूदा ढांचा असुरक्षित संचालन के बजाय काम बंद रहने की अवधि (डाउनटाइम) के लिए दंडित करता है और रखरखाव के लिए की गई कार्यबंदी (शटडाउन) को पुरस्कृत करता है। शक्ति संयंत्र में हुए हादसे जैसी घटनाएं इस बात का भी सबूत हैं कि निरंतर यंत्रिकरण (इंस्ट्रूमेंटेशन) और जांच के बजाय निर्माण संबंधी मानकों पर ढांचे का ध्यान केंद्रित करना कारगर नहीं है। केंद्र सरकार का व्यावसाय करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित करने से औचक सरकारी निरीक्षणों की जगह पर स्व-प्रमाणीकरण और निर्धारित तीसरे-पक्ष द्वारा जांच को बढ़ावा मिला है।

महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होने वाला

सरकार परिसीमन की आड़ में भारत का निर्वाचक मानचित्र बदल देना चाहती है, लेकिन इससे महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होने वाला है, संसदीय सीटों का परिसीमन देश द्रोह है और विपक्ष इसे किसी कीमत नहीं होने देगा सरकार लोक सभा सीटों का परिसीमन और विधायिका में महिलाओं का आरक्षण जिस तरह से देना चाहती है, वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों पर हमला है। विपक्षी सदस्य इसका कड़ा विरोध करते हैं, आप ओबीसी को, दलितों को हिन्दू तो कहते हैं, पर सत्ता में उन्हें स्थान नहीं देते, कार्पोरेट में ओबीसी, दलित कहाँ हैं, शिक्षा क्षेत्र में वंचित वर्ग कहाँ है, निजी क्षेत्र में ओबीसी-दलित कहाँ हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से वंचित वर्गों को हटाय जा रहा है।

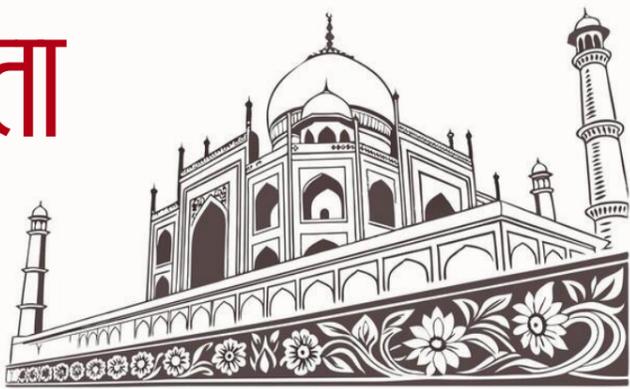
-राहुल गांधी, नेता विपक्ष, लोकसभा

धरोहरों में धड़कता भारतीय इतिहास

विश्व धरोहर दिवस, जिसे आधिकारिक रूप से 'स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस' कहा जाता है, मानव सभ्यता की स्मृतियों और भविष्य की जिम्मेदारियों के बीच सेतु का प्रतीक है। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा स्थापित यह दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को हमें यह स्मरण कराता है कि इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि पत्थरों, गुफाओं, नदियों, जंगलों और स्मारकों में जीवित रहता है। यह उन कहानियों का जीवंत संग्रह है, जिन्हें समय ने तराशा है और जिन्हें संरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत, जो हजारों वर्षों की सतत सभ्यता का वाहक रहा है, अपनी विविधता, गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण विश्व धरोहर मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान रखता है।

वर्तमान में भारत के पास 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसे वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में स्थापित करते हैं और यह दर्शाते हैं कि भारत केवल अतीत का संग्रहालय नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति के अद्भुत संतुलन का जीवंत उदाहरण है। भारत की सांस्कृतिक धरोहरों में ताजमहल की श्वेत संगमरमर में उकेरी गई प्रेमगाथा, कुतुब मीनार की स्थापत्य भव्यता, खजुराहो मंदिर की कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम तथा अजंता और एलोरा गुफाओं की भित्ति चित्रों और शिल्पकला की अजूबी परंपरा शामिल हैं। यह केवल स्मारक नहीं बल्कि भारतीय चेतना की परतों को खोलने वाली जीवित कृतियां हैं, जो धर्म, दर्शन, कला और विज्ञान के समन्वय को प्रस्तुत करती हैं। इसी तरह हमें अपनी महाबलपुरम जैसे स्थल यह प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारत में स्थापत्य, जल प्रबंधन और खगोल विज्ञान कितने उन्नत स्तर पर थे। प्राकृतिक धरोहरों की बात करें तो भारत की जैव विविधता विश्व में अद्वितीय है। काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट और वैली ऑफ फ्लॉवर्स

नेशनल पार्क जैसे स्थल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक हैं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह क्षेत्र हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रकृति और मानव का संबंध प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि सह-अस्तित्व का होना चाहिए। भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल कंचनजंघा नेशनल पार्क इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार प्रकृति और संस्कृति एक-दूसरे में घुल-मिलकर एक समग्र विरासत का निर्माण करती हैं। यहां के पर्वत, मिथक, स्थानीय आस्थाएं और पारंपरिक ज्ञान इस क्षेत्र को केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विशिष्ट बनाते हैं। विश्व धरोहर सूची में किसी स्थल का शामिल होना केवल सम्मान नहीं बल्कि एक कठोर और बहुआयामी प्रक्रिया का परिणाम होता है। पहले किसी स्थल को 'टेन्टेड लिस्ट' में शामिल किया जाता है, फिर विशेषज्ञों द्वारा उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य और संरक्षण संबंधी पहलुओं का गहन मूल्यांकन किया जाता है। जब वह सभी मानकों पर खरा उतरता है, तभी उसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सूची में शामिल प्रत्येक स्थल मानवता के लिए असाधारण सांस्कृतिक मूल्य रखता हो। हाल के वर्षों में भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 2024 में असम के मोइदा-अहोम राजवंश की दफन प्रणाली को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया जबकि 2025 में मराठा सैन्य परिश्रमों को यह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। यह दोनों उदाहरण यह दर्शाते हैं कि भारत की विरासत केवल प्राचीन मंदिरों और स्मारकों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें विविध ऐतिहासिक परंपराएं और क्षेत्रीय पहचान भी शामिल हैं। भारत की धरोहरें केवल राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं कहती बल्कि आम जनजीवन की रचनात्मकता, विश्वास और सामाजिक संरचना को भी अभिव्यक्त करती हैं। नालंदा विश्वविद्यालय



और विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्र यह दर्शाते हैं कि भारत कभी वैश्विक ज्ञान का केंद्र रहा है, जहां दुनियाभर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसी प्रकार भीमबेटका की गुफाएं मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों की झलक प्रस्तुत करती हैं, जहां हजारों वर्ष पुराने चित्र आज भी संवाद करते प्रतीत होते हैं। हालांकि इस गौरवशाली विरासत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अतिक्रमण और अनियंत्रित पर्यटन कई धरोहर स्थलों को अस्तित्व पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। ताजमहल के आसपास बढ़ता वायु प्रदूषण और काजीरंगा नेशनल पार्क में मानवीय हस्तक्षेप इस बात के उदाहरण हैं कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये धरोहरें केवल स्मृतियों में सिमट सकती हैं।

इस दिशा में भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार संरक्षण और पुनरुद्धार के कार्यों में सक्रिय है। 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' जैसी योजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों को भी संरक्षण में भागीदार बनाया जा रहा है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से 'वर्चुअल हेरिटेज वॉक' जैसी पहलें नई पीढ़ी को धरोहरों से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। फिर भी, केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। धरोहर संरक्षण को जनआंदोलन बनाना होगा। जब तक स्थानीय समुदाय स्वयं इन स्थलों को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानेंगे, तब तक संरक्षण के प्रयास अधूरे रहेंगे। विश्वभर जैसे समुदायों का उदाहरण यह दर्शाता है कि यदि समाज जागरूक हो तो वह प्रकृति और विरासत दोनों की रक्षा कर सकता है। भारत की कई ऐसी धरोहरें भी हैं, जो अभी यूनेस्को की सूची

श्वेता गोयल



में शामिल नहीं हैं लेकिन उनकी महत्ता किसी भी फिट से कम नहीं है। वाराणसी की प्राचीनता, मथुरा-वृंदावन की सांस्कृतिक जीवंतता, उज्जैन की धार्मिक परंपरा और लोककला झील की पारिस्थितिक विशिष्टता यह दर्शाती है कि भारत की विरासत केवल सूचीबद्ध स्थलों तक सीमित नहीं है बल्कि हर क्षेत्र, हर संस्कृति और हर परंपरा में समाई हुई है। आज के समय में, जब वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद के प्रभाव में समाज तेजी से बदल रहा है, यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। धरोहरें केवल अतीत का अवशेष नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली प्रेरणा हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि विकास केवल आधुनिकता में नहीं बल्कि परंपरा और नवाचार के संतुलन में निहित है। भारत की धरोहरों में इतिहास पत्थरों में दर्ज है लेकिन उनका अर्थ जीवित है। वे हमें हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी सामूहिक चेतना से जोड़ती हैं। इन्हें संरक्षित करना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को संवारना है। यह जिम्मेदारी जितनी नए स्थलों को अपनी पहचान की भी है। यही वह संवाद है, जो धरोहरों को अमर बनाता है। भारत की 44 विश्व धरोहरें इसी अमर संवाद की प्रतीक हैं, एक ऐसा संवाद, जो अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक निरंतर प्रवाहित हो रहा है।

भारत का फार्मा सेक्टर: युवाओं के लिए नया आकाश

हम उद्योग-आकाश मिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। इसी दिशा में, विश्व आर उद्योग के बीच टालमेल बिठाने के लिए नाईपर और उद्योग के बीच 356 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही स्किल डेवलपमेंट मिशनो के माध्यम से छात्रों को सीधे कंपनियों के साथ जुड़ने के मौके दिए जा रहे हैं। इससे न केवल युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत एक ग्लोबल इनावेशन हब बनेगा।

भारत आज दुनिया की रफार्मसीर के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर चुका है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप अब हम केवल जेनेरिक दवा बनाने वाले देश से आगे बढ़कर एक रचनाकार-आधारित वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य ऐसी नीतियां बनाना है जिससे देश के हर नागरिक कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण दवाएं से मिल सकें। साथ ही सरकार निरंतर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही है और भारतीय फार्मा उद्योग को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काम कर रही है। भारत की अब तक की सफलता उसकी उत्पादन क्षमता, लागत दक्षता और गुणवत्ता मानकों पर आधारित रही है। विश्व की लगभग 20 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं और 60 प्रतिशत वैक्सीन आपूर्ति के साथ देश ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 8 से 10 वर्षों में देश को उच्च-मूल्य, नवाचार-आधारित बायोफार्मा और उन्नत चिकित्सीय उत्पादों का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसकी आधारशिला के रूप में हालिया केंद्रीय बजट में घोषित रुपये 10,000 करोड़ की 'बायोफार्मा शक्ति' पहल महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार आधारित उद्योगों और अगली पीढ़ी की दवाओं के विकास को गति प्रदान करेगा। आर्थिक आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं कि

भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग वर्तमान में 50 अरब डॉलर का है। जिस रफार्म से हम आगे बढ़ रहे हैं, 2030 तक इसके 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की पूरी संभावना है। इसे केवल संख्या नहीं, बल्कि देश के लाखों युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के रोडमैप के तौर पर भी देखने की जरूरत है। वर्तमान में फार्मास्युटिकल उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। 2030 तक हेल्थकेयर और फार्मा क्षेत्र में 20 से 25 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। बायोफार्मा, मेडटेक और क्लीनिकल रिसर्च जैसे उभरते क्षेत्रों ने संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। हमारी सरकार का मानना है कि युवाओं की सफलता की नींव एक मजबूत शैक्षणिक ढांचे पर टिकी होती है। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बजट में फार्मा सेक्टर के लिए और भी कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने देश में तीन नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, वर्तमान में कार्यरत सात नाईपर संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। इन सात संस्थानों में एंटी-बायोलॉजिकल रिसर्च का स्थापना की गई है, जो अनुसंधान और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से विशेष क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, नाईपर मोहाली में एंटी-बायोलॉजिकल रिसर्च और एंटी-बैक्टीरियल दवाओं की खोज एवं विकास, नाईपर अहमदाबाद में मेडिकल डिवाइसेज, नाईपर हैदराबाद में बक ड्रग्स, नाईपर कोलकाता में

फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण, नाईपर रायबरेली में नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नाईपर गुवाहाटी में फाइटोफार्मास्युटिकल्स तथा नाईपर हाजीपुर में बायोलांजिकल थैरेप्यूटिक्स पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों का सीधा लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। नाईपर केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं रह जाएंगे, बल्कि वे ऐसे केंद्र बनेंगे जहां छात्र उद्योग की वास्तविक चुनौतियों पर काम करेंगे। इससे हमारे छात्र केवल जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर और नवाचारी बनेंगे। बदलते दौर में काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अनुमान है कि 2030 तक फार्मा सेक्टर के लगभग 30-35 प्रतिशत कार्यबल को री-स्किलिंग यानी नए कौशल सीखने की जरूरत होगी। केयर डिलीवरी, रिसर्च और मैनुफैक्चरिंग की परिभाषाएं बदल रही हैं। डेटा विश्लेषण, डिजिटल हेल्थ और नियामक मामलों में उच्च कौशल वाले युवाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी। हमारी सरकार का ध्यान इसी स्किल गैप को भरने पर है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र क्लीनिकल रिसर्च और अनुसंधान और विकास में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करें। शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को कम करना हमारी प्राथमिकता है। जब तक हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम और उद्योग की जरूरतें एक समान नहीं होंगी।

-अनुप्रिया पटेल

(लेखक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं)

नोएडा में अशांति: कारखाना मालिकों को सबक लेने की जरूरत

नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में बीते 13 अप्रैल को जो घटना घटी, वह केवल एक स्थानीय प्रदर्शन नहीं थी। फेज-2 के होजरी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 60, 62, 63 और आसपास के दर्जनों कारखानों के हजारों मजदूर वृद्धि, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, साप्ताहिक छुट्टी, बोनस और शिकायत निवारण समिति जैसी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। शुरू में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन था, लेकिन जल्द ही पथराव, वाहनों में आगजनी, संपत्ति तोड़फोड़ और पुलिस के साथ टकराव का रूप ले लिया। पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। सैकड़ों लोग घायल हुए, दर्जनों वाहन जलाए गए और सैकड़ों मजदूरों की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत न्यूनतम मजदूरी में 21 प्रतिशत की अंतरिम वृद्धि की घोषणा कर दी, लेकिन आग बुझने में समय लगा। यह घटना मात्र नोएडा की नहीं है। यह पूरे देश के लिए एक बड़े संदेश की तरह है। आज भारत मैनुफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर श्रमिक-प्रबंधन संबंधों को नजरअंदाज किया गया तो नोएडा जैसी स्थिति कहीं भी दोहराई जा सकती है। मुख्य वजह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच न्यूनतम मजदूरी का बड़ा अंतर था। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अनुभवी मजदूरों के वेतन में करीब 35 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। अकुशल श्रमिकों के वेतन को 14,000 रूपए से बढ़ाकर 19,000 रूपए तक कर दिया गया। नोएडा के मजदूरों को यही खबर मिली और उन्होंने मांग की कि उनका वेतन भी उसी स्तर पर हो। वर्तमान में



नोएडा में कई कारखानों में अनुभवी मजदूरों को 11-13 हजार रूपए मासिक मिल रहे थे, जबकि महंगाई, क्रिया, राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च में आसमान छू लिया है। साथ ही लंबे काम के घंटे, ओवरटाइम का सिंगल रेट, वेतन स्लिप न मिलना और यौन उत्पीड़न समिति जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने आक्रोश को भड़काया। सोशल मीडिया पर 'हरियाणा मॉडल' की खबरें तेजी से फैलीं। कुछ बाहरी तत्वों ने भी इसे भड़काने की कोशिश की, लेकिन मूल समस्या आर्थिक थी। तीन-चार दिन के शांत प्रदर्शन के बाद 13 अप्रैल को हिंसा भड़क गई। पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग किया, लेकिन स्थिति बिगड़ चुकी थी। सरकार ने बार में 1 अप्रैल से लागू होने वाली वेतन वृद्धि की घोषणा की, फिर भी कई ग्रामीण इलाकों और पूर्वी राज्यों से आते हैं। वे परिवार को पैसा भेजने के लिए कम वेतन पर भी काम करते हैं, लेकिन महंगाई ने उनका सब्र तोड़ दिया। सोशल मीडिया

आय में कमी खाने-पीने, आवास और परिवहन का खर्च तेजी से बढ़ा है, लेकिन वेतन वृद्धि धीमी रही। विशेषकर अनुबंधित और टेकदार मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। श्रम कानूनों का अधूरा कार्यान्वयन चार नए श्रम संहिताओं का उद्देश्य सुविधा देना था, लेकिन कई राज्यों में उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया गया। न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा समय पर नहीं होती। प्रबंधन की उदासीनता कई कारखाने एमएसएमई क्षेत्र के हैं। मालिक लागत बचाने के चक्कर में वेतन, बोनस और सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। संवाद की कमी भी रहती है। जब हरियाणा में वेतन बढ़ा, तो नोएडा के मालिकों ने इसे 'स्थानीय मुद्दा' मानकर नजरअंदाज कर दिया। नोएडा जैसे क्षेत्रों में ज्यादातर मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों और पूर्वी राज्यों से आते हैं। वे परिवार को पैसा भेजने के लिए कम वेतन पर भी काम करते हैं, लेकिन महंगाई ने उनका सब्र तोड़ दिया। सोशल मीडिया

कर्मचारियों के हक

नोएडा से सबक लेकर देश भर के कारखाना मालिकों को तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए।

- हर साल महंगाई के आधार पर 10 से 20 फीसदी वेतन बढ़ोतरी का फॉर्मूला तय करें।
- वेतन सलाह पर और रिलेफ के साथ दें।
- ग्रेविएंस कमेटी, वर्कर्स वेलफेयर कमेटी बनाएं।
- मासिक बैठकें रखें।
- ओवरटाइम, पीएफ, ईएसआई, बोनस, छुट्टियां जैसे सभी नियमों का पालन करें।
- मजदूरों को ट्रेनिंग दें ताकि वे ज्यादा उत्पादक बनें व बेहतर वेतन का हकदार हों।
- काम का माहौल सुरक्षित और सम्मानजनक बनाएं।
- यौन उत्पीड़न समिति अनिवार्य रूप से सक्रिय रखें।
- राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर लंबी अवधि की मजदूरी नीति बनाएं।

और सूचना का प्रसार ऐसा होने लगा कि एक जिले की खबर दूसरे जिले में तुरंत पहुंचने लगी। जिस कारण तुलना

राजनीश कपूर



आसान हो गई है। इसी तरह की घटनाएं पहले गुरुग्राम, चेन्नई, कोयंबटूर और अहमदाबाद में भी देखी गई हैं। सवाल उठता है कि क्या दोष किसी एक पक्ष का है? उल्लेखनीय है कि कई फैक्ट्रियां लाभ कमा रही हैं, लेकिन मजदूरों को न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दे पा रही। संवाद की जगह दमन का रवैया अपनाया जाता है। वहीं सरकार की बात करें तो उनके द्वारा न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा में देरी करना। पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय की कमी।

श्रम विभाग की कमजोर निगरानी, आदि जैसे कई कारण हैं जो सरकार को भी सवालियों के घेरे में लाते हैं। वहीं मजदूरों की बात की जाए तो हिंसा कभी जायज नहीं होती। वाहनों में आग लगाना, पथराव और संपत्ति तोड़फोड़ से उनकी अपनी मांगें कमजोर होती हैं। ऐसे में कुछ बाहरी उकसावे वाले तत्व इन सब का फायदा उठा लेते हैं। कई जगह यूनियन राजनीतिक रंग ले लेती हैं और संवाद की बजाय आंदोलन को बढ़ावा देती हैं। वास्तव में दोष 'व्यवस्था' का है, जिसमें त्रिपक्षीय संवाद (सरकार-प्रबंधन-श्रमिक) कमजोर हो गया है। (ये लेखक के निजी विचार हैं)



प्रयागराज। भीषण गर्मी में पानी के टैंकर के ऊपर से पानी की बोतलें भरता व्यक्ति।

मार्को रुबियो-एट्टे कपूर के बीच युद्ध विराम व होमरुज को लेकर चर्चा

लंदन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कपूर के साथ अमेरिकी-ईरान युद्ध विराम और होमरुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने बताया कि दोनों नेताओं ने युद्ध विराम के अगले कदमों की समीक्षा की और जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वाणिज्यिक जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और ईरान के बीच वर्तमान संघर्षविराम 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उल्लेख किया कि यह अभी भी अनिश्चित है कि युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, लेकिन उन्होंने चल रही बातचीत के बारे में आशा व्यक्त की।

मैक्रों ने इजरायल व लेबनान युद्धविराम का समर्थन किया

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने इजरायल और लेबनान के बीच दस दिनों के युद्धविराम का 'पूर्ण समर्थन' किया है। मैक्रों ने हालांकि इस समझौते को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि सैन्य अभियानों के जारी रहने से यह युद्धविराम कमजोर पड़ सकता है। मैं सीमा के दोनों ओर नागरिक आबादी की सुरक्षा की अपील करता हूँ। हिजबुल्लाह को अपने हथियारों का त्याग करना चाहिए और इजरायल को लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करते हुए युद्ध रोकना चाहिए। इजरायल और लेबनान दोनों ने इस युद्धविराम का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे 'ऐतिहासिक शांति समझौता' करने का अवसर' बताया है। यह समझौता फिलहाल दस दिनों के लिए है, जिसे बातचीत में प्रगति होने पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्यूबा के राष्ट्रपति की ट्रम्प को दो टूक

हवाना। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कैनेल ने कहा कि क्यूबा नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करे। उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता है तो उनका देश लड़ने के लिए तैयार है। डियाज-कैनेल ने यह बात एक रैली में कही, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। यह रैली क्यूबा की क्रांति के 65 साल पूरे होने पर आयोजित की गई थी, जब क्यूबा ने खुद को समाजवादी देश घोषित किया था। डियाज-कैनेल ने कहा, यह बेहद चुनौतीपूर्ण समय है और हमें एक बार फिर गंभीर खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, जैसे 16 अप्रैल 1961 को था। इन खतरों में (संभावित) सैन्य हमला भी शामिल है। हम यह नहीं चाहते, लेकिन इससे बचने के लिए तैयारी करना हमारा कर्तव्य है और अगर यह टालना संभव न हो, तो हमें इसे हराना होगा। उन्होंने यह बात ऐसे समय में कही, जब

अमेरिका ने सैन्य आक्रामकता दिखाई, तो लड़ाई लड़ेगा देश, हमें एक बार फिर गंभीर खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा



डियाज कैनेल ने यह बात एक रैली में कही, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे।

दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। अमेरिका की ऊर्जा नाकेबंदी के कारण क्यूबा का संकट और गहरा गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रम्प ने कहा था कि ईरान के साथ जंग खत्म होने के बाद उनका प्रशासन क्यूबा पर फोकस कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम इसे खत्म करने के बाद क्यूबा की ओर भी जा सकते हैं। उन्होंने क्यूबा को विफल देश बताया और कहा कि यह लंबे समय से खराब तरीके से चलाया जा रहा है। जनवरी के शुरुआत में

ट्रम्प ने पहले भी क्यूबा में दखल की धमकी दी थी, जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया और वहां से आने वाले तेल की आपूर्ति रोक दी। कुछ हफ्तों बाद ट्रम्प ने उन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी, जो क्यूबा को तेल बेचते हैं या उपलब्ध कराते हैं। ट्रम्प और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के माता-पिता 1950 के दशक में क्रांति से पहले क्यूबा से प्रवास कर गए थे। दोनों ने क्यूबा की सरकार को अक्षम और दमनकारी बताया है। डियाज-कैनेल ने उन पर आरोप लगाया कि वे एक ऐसा 'कहानी' बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा क्यूबा असफल देश नहीं है। क्यूबा एक घिरा हुआ देश है। क्यूबा एक ऐसा देश है, जो कई तरह के हमलों का सामना कर रहा है। इनमें आर्थिक युद्ध, कड़वी नाक-बंदी और ऊर्जा नाकेबंदी शामिल हैं। उन्होंने कहा क्यूबा एक ऐसा देश है जिसे धमकाया जाता रहा है, लेकिन वह झुकता नहीं है। हर चीज के बावजूद समाजवाद की वजह से क्यूबा एक ऐसा देश है, जो संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है और याद रखिए, यह देश जीतकर रहेगा। क्यूबा और अमेरिका दोनों ने 1950 के दशक में क्रांति से पहले क्यूबा से प्रवास कर गए थे। दोनों ने क्यूबा की सरकार को अक्षम और दमनकारी बताया है।

संक्षिप्त समाचार

आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 380 से अधिक ठिकानों को बनाया निशाना
यरूशलेम। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि उसने पिछले 24 घंटों में लेबनानी शिया आंदोलन हिजबुल्लाह के 380 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर कहा कि पिछले 24 घंटों में, आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में सक्रिय जमीनी बलों के अभियानों का समर्थन करने के लिए हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के 380 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। आईडीएफ ने कहा कि हमलों में हिजबुल्लाह के सदस्यों, मुख्यालयों और लाॅन्चरों को निशाना बनाया गया।

इंडोनेशिया के बोरिनियो द्वीप पर हेलीकॉप्टर क्रैश, आठ की मौत
जकार्ता। इंडोनेशिया के बोरिनियो द्वीप पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पाय आयल के बागानों के बीच उड़ान भर रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी। यह हेलीकॉप्टर 'पीटी मैथ्यू एयर नुसंतारा' कंपनी का था और इसका माडल एयरबस एफ130 था। इसने पश्चिमी कालीमंतन प्रांत के मेल्बि जिले से उड़ान भरी थी।

लव एंड वॉर 21 जनवरी 2027 को होगी रिलीज
मुंबई। रणवीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर 21 जनवरी 2027 को दुनियाभर में रिलीज होगी भव्य स्तर पर बनी लव एंड वॉर, संजय लीला भंसाली की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। अपनी भव्य कहानी और इमोशनल गहराई के साथ, यह फिल्म भारत की सबसे बड़ी लव सागा और इंडियन सिनेमा की सबसे शानदार रोमांटिक फिल्मों में से एक बनकर उभर रही है।

ईरान से समझौते को खुद पाक जाएंगे ट्रम्प!

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- ईरान के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, टिप्पणी को उनके यू-टर्न की तरह भी पेश किया जा रहा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 40 दिनों से अधिक की जंग के बाद तनावपूर्ण शांति के बीच आई इस टिप्पणी को उनके यू-टर्न की तरह भी पेश किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी टिप्पणी की। ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 'दोस्त' बताते हुए कहा कि मोदी के साथ फोन पर उनकी बातचीत 'बहुत अच्छी' रही।



मोदी के साथ फोन पर उनकी बातचीत 'बहुत अच्छी' रही: ट्रम्प

पीएम मोदी ने भी ट्रम्प के फोन काल की पुष्टि की थी। गौरतलब है कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने होमरुज जलडमरूमध्य को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी दोनों नेताओं के बीच की बातचीत को सकारात्मक बताया। वहीं ट्रम्प ने यह भी कहा है कि अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत और ईरान से इतर इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम पर भी बयान दिया। उन्होंने लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में 10वां युद्ध रोकने में सफलता हासिल की है। डोनरो सिद्धांत जुमले का इस्तेमाल ट्रम्प की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की महत्वपूर्ण शांति वार्ता की मंजबूती करने की तैयारी कर रहा है। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त करना है। इस युद्ध ने दुनिया भर में ऊर्जा की आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले हफ्ते हुई पहली सीधी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई थी। हालांकि, दोनों पक्ष अभी दो हफ्ते के अस्थायी युद्धविराम का

पालन कर रहे हैं। यह युद्धविराम 22 अप्रैल को समाप्त होगा। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर दोनों देशों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारिक ने सूत्रों ने शुक्रवार को कहा, दोनों पक्षों को बातचीत की टैबल वापस लाने के लिए तेजी से डिप्लोमैटिक काम हुआ। इस शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनिर काफी सक्रिय हैं।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मूनरो ने यूरोपीय उपनिवेशीकरण बंद करने का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में किसी भी हस्तक्षेप को अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी बढ़ाने जैसे कृत्य के रूप में देखा जाएगा। बीते 200 साल से अधिक समय से इस नीति को डोनरो सिद्धांत की तरह पेश किया जा रहा है। अब गाह-ब-गाह ट्रम्प की नीतियों को भी इसी जुमले के आधार पर पेश किया जाता है। वहीं ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ बहुत जल्द जीत का दावा किया। उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमताओं में भारी गिरावट का उल्लेख किया। ट्रम्प ने ईरान को कठिन, स्मार्ट देश बताया, पर कहा उसकी नौसेना खत्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 158 जहाज समुद्र में डूब चुके हैं। ट्रम्प ने ईरानी कमांडर घोलमरजा सुलेमानी को निशाना बनाने का भी जिक्र किया। उन्होंने सुलेमानी को 'सबसे बुरे आतंकवादियों में से एक' बताया, उस पर अमेरिकी सैनिकों पर हमलों का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच, ट्रम्प ने ईरान के साथ युद्धविराम विस्तार पर अनिश्चितता जताई। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ जल्द ही एक समझौता हो सकता है। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना राष्ट्रपति के दौर में इस्तेमाल 'मोनरो सिद्धांत' से प्रेरित है। दरअसल, 1823 में

ट्रम्प ने अपनी आर्थिक नीतियों का बचाव किया

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतों के बीच गुरुवार को लास वेगास में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी सरकार के आर्थिक रिकार्ड का बचाव किया। श्रम विभाग की हालिया रिपोर्ट में पिछले महीने महंगाई में 0.9 प्रतिशत का बढ़ोतरी दिखाई गई है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे बड़ी उछाल है। ट्रम्प ने इस रिपोर्ट की सत्यता पर संदेह जताते हुए इसे ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में अस्थायी वृद्धि का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह मत भूलिए कि ईंधन और ऊर्जा की कीमतों के कारण हमें कुछ 'फर्जी महंगाई' का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि ये बढ़ी हुई कीमतें 'अल्पकालिक' हैं और उन्होंने अमेरिकियों से आने वाले सप्ताह के घटनाक्रमों पर नजर रखने का आग्रह किया। गौरतलब है कि खाड़ी क्षेत्र में ईरान के जवाबी हमलों के बाद ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। अगले दौर की वार्ता सप्ताहांत में होने की संभावना है।

नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू

काठमांडू। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया है, जो 2006 से लेकर 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। जांच के दायरे में 2005-06 के बाद के सभी 7 प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इनमें सुशील कोइराला, पुष्प कमल देवल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, कपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउवा शामिल हैं। इसके साथ ही दो अंतरिम सरकारों के प्रमुख खिलराज रेग्मी और सुशीला कार्की भी जांच के दायरे में आएंगे। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी आएंगे। इसके अलावा

अमेरिका में वैज्ञानिकों के लापता होने पर ट्रम्प बोले- मामला गंभीर जांच का दिया आदेश

वाशिंगटन। अमेरिका में संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों के लापता या मृत होने की रिपोर्टों को लेकर चिंता बढ़ गई है। ट्रम्प ने इस मामले को 'गंभीर' बताया और जांच के आदेश दिए। न्यायदंड विभाग के प्रवक्ताओं ने बताया कि ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर बैठक की है और जल्द ही इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ बेहद महत्वपूर्ण लोग इससे जुड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2023 के बाद से कम से कम 10 वैज्ञानिक या सरकारी कर्मचारी, जो एडवॉंस डिफेंस और एयरोस्पेस रिसर्च में काम कर रहे थे, लापता हो गए हैं या उनकी मौत हो गई है। इन मामलों में लास एलामोस नेशनल लैबोरेटरी, नासा की जेट प्रोपल्शन लैब और डफ्फ के प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर से जुड़े लोगों का जिक्र किया गया है।

अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा

दमिश्क। करीब 12 साल की सैन्य मौजूदगी के बाद अमेरिकी सेना सीरिया से अपने सभी सैनिक निकाल लिए हैं और सैन्य ठिकाने खाली कर दिए हैं। अप्रैल 2026 में हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी कार्गो निकल गया। इसके बाद सीरियाई सरकार ने सभी बेस अपने कब्जे में ले लिए। सीरियाई विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह कदम देश को एकजुट करने और पूरे इलाके पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में बड़ा मोड़ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि करीब 2000 सैनिक जार्डन जा रहे हैं। अमेरिका का इराका, रूमेलान और देहर एज-जोर में मौजूद कम से कम सात बड़े ठिकाने खाली किए। आखिरी ठिकाना कसराक एयरबेस था। अब इस पर सीरियाई सेना का नियंत्रण है। हसाका प्रांत के ग्रामीण इलाके में स्थित कसराक



जॉर्डन लौट रहे सैनिक, सरकार बोली- अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा

बेस है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद इसे सीरियाई सरकारी बलों को सौंप दिया गया। इस बीच, सीरिया सरकार और एसडीएफ के बीच हुए समझौते के बाद कुर्द लड़ाकों को राष्ट्रीय सेना में शामिल किया जा रहा है। हसाका और कामिशीली जैसे शहरों में सरकारी बल तैनात हो चुके हैं और सीमाई इलाकों पर भी दमिश्क का नियंत्रण बढ़ा है। इसी साल दोनों पक्षों के बीच झड़पें भी हुई थीं, जिसके बाद मार्च में एक नया समझौता हुआ। इसके तहत एसडीएफ और कुर्द प्रशासनिक ढांचे को धीरे-धीरे रण्य में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सीरिया ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कामिशीली जैसे शहरों में सरकारी बल तैनात हो चुके हैं और सीमाई इलाकों पर भी दमिश्क का नियंत्रण बढ़ा है। इसी साल दोनों

इजरायल-लेबनान के बीच युद्धविराम लागू

आक्रामक सैन्य अभियानों को रोकने पर सहमत हुए दोनों देश

तेल अवीव/बेरुता। इजरायल और लेबनान 10 दिनों के लिए संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं, जो पूर्वी समय अनुसार 16 अप्रैल शाम पांच बजे (भारतीय समयानुसार 17 अप्रैल तड़के 3:30 बजे) से प्रभावी हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा कि लेबनान के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है। अच्छी चीजें हो रही हैं। ट्रम्प ने फिर से दावा किया कि उन्होंने दुनिया भर में नौ युद्धों को सुलझाया है और यह दसवां होगा। उन्होंने कहा कि तब चलिए इसे पूरा करते हैं। इस अस्थायी युद्धविराम का उद्देश्य शांति समझौते की दिशा में बातचीत के लिए अवसर प्रदान करना है। यह समझौता ट्रम्प द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और



लेबनान के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है: ट्रम्प

जताई है। इस अवधि के दौरान इजरायली बल दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर के 'सुरक्षा क्षेत्र' में बने रहेंगे। पहले ही युद्धविराम आधिकारिक तौर पर प्रभावी है लेकिन लेबनानी सेना ने आज सुबह दक्षिणी गांवों में इजरायल द्वारा कई हमलों की सूचना दी। इस बीच, इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 24 घंटों के दौरान लेबनान में हिजबुल्लाह के 380 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि वे तभी तक संघर्षविराम का 'पालन' करेंगे जब तक इजरायली हमले बंद रहेंगे। यह संघर्षविराम एक व्यापक क्षेत्रीय राजनयिक प्रयास का हिस्सा है जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच अलग से चल रहा दो सप्ताह का युद्धविराम भी शामिल है।

यौन समस्याएं विशेषज्ञ

यौन समस्याओं के विशेषज्ञ

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

डा. सम्राट

नशामुक्ति, शराब, बीडी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन कैप्सूल अफीम, चरस, डोडे पोस्ट इंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज।

नावल्टी सिनेमा चौक मुजफ्फरनगर (यू.पी.)

M-941221108

देश/विदेश से एम.बी.बी.एस. एवं स्टीडी वीजा के लिए सम्पर्क करें

अनुम कलीम (एम.डी.) 8384872313 9457439020

M.B.B.S./M.D.

BDS, BAMS, BUMS, BEMS

Abroad Admission & Counselling For India

- Top Govt. Universities.
- MCI, WHO Approved Universities.
- Indian Hostel & Mess Available.
- Lowest Price Packages.
- Boys/Girls Hostels Are Separates Available.

अपना एम.बी.बी.एस. 25 से 27 लाख में पूरा करें

जिसमें ट्यूशन फीस, होस्टल फीस, खाना 3 टाईम (वेज/नॉनवेज), वीजा एक्सटेंशन, इश्योरेंस, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्डरी, एफ.एम.जी. ई. कॉविंग, 15 इंडियन बेट फंक्लटी के द्वारा वीजा रखी है 471 वर्षों जनवरी एफ.एम.जी.ई. एकजाम में पास हुऐ (अन्य कोई खर्चा नहीं)

www.mbbsbijnor.com

ADD : MBBS ABROAD CONSULTANCY, MOIN KA CHAURAH, CHAHSHIREEN JAMA MASJID, B-21, BIJNOR (U.P)